केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से दैनिक भास्कर की विशेष मुलाकात

निजी वाहनों को टोल से मुक्ति देने के लिए प्रयास

कहा-टोल नाकों पर हर साल 88 हजार करोड़ का ईंधन बेकार जल जाता है, रास्तों का जाल बिछाने के साथ ही जलमार्ग यातायात भी बढ़ाएंगे

विकास झाडे | नई दिल्ली

देशभर में नए मार्गों के लिए टोल टैक्स वसूली आवश्यक है। निजी वाहन चालकों में इसे लेकर खासा गुस्सा रहता है। व्यावसायिक वाहनों की अपेक्षा निजी वाहनों से मिलने वाली टोल राशि बहुत ही कम है। ऐसे लोगों के हित में निर्णय लेकर, निधि की भरपाई करने के अन्य मार्ग पर विचार चल रहा है। यह बात कही है केंद्रीय राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। इन्होंने निजी वाहनों को टोलमुक्त करने की मन की बात भास्कर से साझा की। टोल नाकों पर खड़े वाहनों से प्रति वर्ष 88 हजार करोड़ रुपए का ईंधन जल जाता है। यह नुकसान रोकने के लिए ई-टोल के बारे में उन्होंने कहा। दैनिक भास्कर को दी विशेष मुलाकात में गडकरी ने दिल खोलकर बातें कीं।

महाराष्ट्र में गठबंधन के काल में 'पुल बनाने वाले' के नाम से जाने जाने वाले गडकरी अब देश में कौन से विकास का सपना देख रहे हैं?

देश के विकास में रास्तों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। हाई-वे बनाने का काम मेरे हिस्से में आता है। बीते वर्षों में भू-संपादन के कारण अनेक मार्गों का निर्माण रुका हुआ था। अनेक जगह रेलवे ओवर ब्रिज का काम रुका पड़ा था। इन सभी बाधाओं को पार कर वर्तमान में 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपए के बंद पड़े हुए 70 से 80 प्रतिशत काम शुरू कर दिए गए हैं। यूपीए सरकार के समय रोज 1 किमी रास्ता बनाने का काम होता था, हमने रोज 30 किमी रास्ते बनाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही सीमेंट-कांक्रीट के रास्ते निर्माण का काम भी होता रहेगा। इससे आने वाले 50 साल तक मेंटेनेंस के काम से छुटकारा मिलेगा। रास्ते बनने के लिए हमें मात्र 120 रुपए में एक सीमेंट बोरी मिल रही है। इस कारण खर्च में बड़ी बचत हो रही है। इसका लाभ राज्य सरकार, महापालिका और अन्य शासकीय संस्थाओं को भी मिलेगा।

हाई-वे पर कुछ सुविधाएं भी देने का प्रयत्न कर रहे हैं क्या?

महामार्गों पर प्रवासियों के लिए दो हजार सेंटर खोलने के लिए निविदाएं भी निकाली गई हैं। यहां होटल, मार्केट और स्वच्छता गृह उपलब्ध कराने जा रहे हैं। ट्रक वालों को अलग तरह की सुविधाएं देंगे। महामार्ग के बीच के स्थान पर ऑप्टिकल फाइबर केबल, इलेक्ट्रिक कार स्पेशल पाइप लाइन और गैस पाइप लाइन डाली जा सकती है क्या, इस सब से टैक्स के रूप में कुछ राशि मिल सकती है क्या, इसके बारे में अभ्यास जारी है। प्रवासियों को अधिक सुविधाएं देना तथा उन्हें कम से कम परेशानी हो, ऐसा मेरा प्रयास है।

छह महीने में आपने अनेक घोषणाएं की हैं, उनमें से किस योजना को प्राथमिकता देंगे?

रुके हुए तथा बाधित सभी तरह के काम हम कर रहे हैं। 40 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाओं की हमने शुरुआत की है। देशभर में रास्ते बनाने के काम में गति लाने के लिए क्रिसेल की रिपोर्ट लागू करने में आई है। सभी घोषणाएं पूरी करना मेरी प्राथमिकता रहेगी।

आपने ई-रिक्शा को मंजूरी दी। मात्र अपना हित साधने का आरोप आप पर लगा है?

देशभर में एक करोड़ से अधिक लोग साइकिल रिक्शा चला रहे हैं। इसमें मनुष्य, मनुष्य को ढो रहा है। मुझे यह अमानुषिक कार्य लगता है। ई-रिक्शा के बाद यह श्रम करना नहीं पड़ेगा। मात्र कुछ लोग स्वार्थ की खातिर आरोप करते हैं, यह गलत है। आरोप करो तो सिद्ध करके भी दिखाओ। ई-रिक्शा निर्माण में मेरा कोई भी रिश्तेदार या पहचान वाला नहीं है। दिल्ली में ई-रिक्शा सर्वाधिक हैं। इस कारण वहां उद्योगों की संख्या बढ़ी है। ई-रिक्शा कानून लागू होता है तो इसे लागू करने, न करने का स्वतंत्र अधिकार राज्यों के पास भी रहेगा। ई-रिक्शा को अब मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत नंबर भी दिए जाएंगे। चालक को 10 दिन का प्रशिक्षण देकर लाइसेंस भी दिया जा सकेगा। रोजगार के लिए यह उत्तम पर्याय हो सकता है।

आप उद्योगों के लिए जोर देते हैं। नए प्रयोग करते हैं। ऐसी पार्श्वभूमि न होते हुए भी आप उद्योगों में पड़ने का विचार कैसे कर लेते हैं?

उद्यमशीलता और उपक्रमशीलता ये दो भिन्न पहलू हैं। देश से गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ इनोवेटिव, अलग हटकर उपलब्ध कराने की जरूरत है। इसलिए मैं नए-नए प्रयोग करता रहता हूं। लोगों को प्रोत्साहित करता रहता हूं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायोडीजल, बायो एनर्जी, हैंडीक्राफ्ट जैसे अनेक क्षेत्रों में मैं काम करता रहता हूं। राजनीतिक लोगों को सत्ता में ही राजनीतिक काम नहीं करना चाहिए, बल्कि सेवा, विकास और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करना चाहिए। ग्रामीण भागों में नई तकनीक, इनोवेशन लाकर लोगों को रोजगार देना चाहिए। इससे निश्चित ही गरीबी दूर होगी। राजनीति तो सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन लाने का प्रभावी माध्यम है। इसी भावना से काम करना चाहिए। आगे मेरी ऐसी ही भूमिका रहेगी।

टोल टैक्स से मुक्ति के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं?

आयएम कोलकाता और टांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं के निकाले गए निष्कर्ष के अनुसार टोल नाकों पर रुके वाहनों से प्रति वर्ष 88 हजार करोड़ रुपए का तेल जल जाता है। इससे निबटने के लिए अभी तक 110 ई-टोल नाके शुरू किए जा चुके हैं। वर्षभर में और 350 ई-टोल नाके शुरू होने वाले हैं। इससे जाम से मुक्ति मिलेगी, तेल और समय की बचत होगी। अच्छे रास्ते बनाने के लिए रुपए तो लगेंगे ही, लेकिन देखा गया है कि टोल को लेकर लोगों में रोष है। ऐसे में लोगों को

टोल से किस तरह मुक्ति दी जाए, इस विषय पर विचार चल रहा है। 2013-14 में देशभर से 11 हजार 400 करोड़ रुपए टोल टैक्स के रूप में प्राप्त हुए। इसमें से 9 हजार 800 करोड़ व्यावसायिक वाहनों से केवल 1600 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। निजी वाहनों से अत्यल्प टोल राशि मिलती है, इन्हीं लोगों में टोल को लेकर अधिक रोष है। भविष्य में इन लोगों के हित में निर्णय लिया जा सकता है। मात्र, ऐसे लोगों के हिस्से की टोल राशि किस मार्ग से वसूल की जाए, किस योजना द्वारा वसूल की जाए, इस बाबत विचार चल रहा है।

महाराष्ट्र में आपने बीओटी का प्रभावी इस्तेमाल किया। देशभर में इस योजना के लिए आप जोर देंगे क्या?

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) यह योजना आनंददायक नहीं है, लेकिन कोई भी दूसरा पर्याय न होने पर लाना पड़ी। आज अनेक दूरस्थ क्षेत्रों में जाने के लिए रास्ते नहीं हैं। वहां पीपीपी योजना में काम नहीं किया जा सकता। इस कारण बड़े शहरों में रास्ते के लिए प्राइवेट इनवेस्टमेंट द्वारा रुपया लाएंगे। वहीं, ग्रामीण, आदिवासी क्षेत्रों व गरीबों के लिए सरकारी रुपया खर्च करने की हमारी योजना है। इससे छोटे कस्बे भी महामार्ग व शहरों से जोड़े जा सकेंगे।

आरोप हैं कि आप ठेकेदारों का पक्ष लेते हैं। गोसीखुर्द गांव के ठेकेदारों के भुगतान के लिए आपने तत्कालीन केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा था?

यह सब गलत बातें हैं। मैंने किसी ठेकेदार का पक्ष नहीं लिया। गोसीखुर्द की योजना में लोगों को पर्याप्त पानी मिले, यही मेरा प्रयास है। विदर्भ के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यह योजना पूरी हुई तो साढ़े तीन लाख एकड़ जमीन पर सिंचाई हो सकेगी। विदर्भ का विकास होगा, मैं वहां का प्रतिनिधि हूं। वहां के किसानों को न्याय मिले, यही मेरी सोच है। ठेकेदारों के बिल मंजूर हों या उन्हें काम मिले, ऐसी भूमिका मेरी कभी नहीं रही। आरोप करने वाले इसे अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए हैं।

आप जितना बोलते हैं, उससे अधिक काम करते हैं, ऐसा कहा जाता है। मोदी सरकार में ऐसा संभव हो पाएगा, ऐसा संभव लगता है क्या?

मैंने जितना कहा है, उसकी अपेक्षा 30 से 40 प्रतिशत अधिक काम करके दिखाया है। मेरी घोषणाएं आप लिखकर रखें, उनमें से यदि मैं एक भी पूरी न कर सका तो जनता से माफी मांग लूंगा। मैं अभ्यास करके ही घोषणा करता हूं। इसके पीछे योजना व इच्छाशक्ति होती है। मेरी योजनाओं में कहीं भी रुकावट नहीं है।

आप हर एक काम की डेटलाइन ठहरा देते हैं। इस साल कितने काम समय सीमा में पूरे कर पाए हैं?

'नहीं हुआ..' यह शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। मेरे काम कभी भी पेंडिंग नहीं रहते। यूपीए सरकार के काल में भी रुके हुए काम पूरे करने में मैं सफल रहा हूं। 2014 में ठहराए गए सभी काम मैंने पूरे किए हैं।

सांसद अपने क्षेत्र के पांच गांव का विकास करें, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना है। मात्र इसके लिए स्वतंत्र राशि न होने को लेकर क्या सांसदों में नाराजगी है क्या?

ग्रामीण भागों में विकास के लिए सरकार की 63 योजनाएं हैं। उन योजनाओं में से हमें विकास करना संभव लगता है। सरकार भी ऐसे कामों को प्रधानता देगी। इसके अलावा राज्य व केंद्र की अन्य योजनाओं में से भी निधि ली जा सकती है। सांसद निधि में से कितना प्रतिशत इसमें खर्च होना चाहिए, इस पर भी विचार चल रहा है। काम करने की इच्छाशक्ति हो तो पैसे की समस्या नहीं आती। विकास करने की दृष्टि, समाज बदलने की संवेदनशीलता और गरीबों का भला करने की भावना लोक प्रतिनिधियों में होना चाहिए।

क्या आपके कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर रोक लगी है?

सौ फीसदी। 1988 का मोटरयान अधिनियम हम ही ला रहे हैं। अगले अधिवेशन में वो लाया जाएगा। इस सब से बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। देश भ्रष्टाचारमुक्त होगा। अब हमने ऑनलाइन परमिट शुरू किए हैं। इस कारण कई शहरों में परिवहन कार्यालय जाने की जरूरत अब रही नहीं। मेरे विभाग में भ्रष्टाचार होने का कहीं भी नहीं लिखा गया।

मैं दिल्ली में ही ठीक हूं

प्रश्न : महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद क्यों ठुकरा दिया।

एक तो आधी दिल्ली में मेरे आने पर दो मत थे। यहां आकर मैं रम गया हूं। मैंने अब गंगा का काम, राष्ट्रीय महामार्ग के काम जैसी भव्य योजनाएं हाथ में ली हैं। इस कारण अब वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसा निर्णय मैंने लिया। मात्र दिल्ली में रहकर भी मैं महाराष्ट्र के विकास के लिए कटिबद्ध रहता।

सभी की सुनते हैं मोदी

ऐसा कहा जाता है कि मोदी के सामने अन्य मंत्री मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करते?

ऐसा बिलकुल नहीं है। अब परिस्थिति अलग है। प्रधानमंत्री सभी की सुनते हैं। हर विभाग का मंत्री अपनी भूमिका उनके सामने रखता है। कोई भी निर्णय सर्वानुमति से होता है। मीडिया कई बार बिना कारण ऐसे विषय उछाल देता है।

जलमार्ग यातायात का प्रमाण बढ़ेगा

प्रश्न : नए साल में आपका एक्शन प्लान क्या होगा?

इंग्लैंड वाटर-वे (जलमार्ग यातायात) को मैं प्राथमिकता दूंगा। चीन में 44 प्रतिशत यातायात पानी में होता है। हमारे यहां यह केवल 3.3 प्रतिशत है। इसे 8 से 10 प्रतिशत तक ले जाने का मेरा प्रयत्न है। यह काम चाहे कठिन है, मैं प्रयत्नशील हूं। गंगा से वाराणसी से हल्दिया तक और उधर उत्तर-पूर्व में जल यातायात व परिवहन शुरू करने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं। दूसरा, प्रतिदिन 30 किलोमीटर रास्ते बनाने का लक्ष्य भी है। अविरल व निर्मल गंगा करने का काम मैं प्राथमिकता से कर रहा हूं।

सत्ता, पद मिले, यह ध्येय नहीं

प्रश्न : संरसंघचालक के माध्यम से आप राजनीति में मजबूत स्थान बना रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है।

यहां मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरे सभी से अच्छे संबंध हैं। सत्ता या पद के लिए मैंने कभी राजनीति नहीं की। गरीब के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ तो किया जाए, ऐसी मेरी मंशा होती है। इसी दृष्टि से मैं काम करता रहा हूं और आगे करता रहूंगा। मैंने किसी को कभी बाँयोडाटा दिया नहीं, कभी पद मांगा नहीं। कुछ नहीं भी मिला तो भी मैं अपना काम करता रहूंगा।

राज्य को मदद दिलवाएंगे

प्रश्न : महाराष्ट्र को अभी तक दुष्काल पैकेज मिला क्यों नहीं?

इस संबंध में मेरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस से बात हो चुकी है। वे जल्द ही दिल्ली आएंगे। विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिमी महाराष्ट्र में फलों के बगीचे आदि की स्थिति विकट है। हम सभी संबंधित मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं। महाराष्ट्र को अधिक से अधिक मदद दिलाने के लिए मैं प्रयत्नशील हूं, रहूंगा।